an>

Title: Need for construction of houses and panchayat bhawans under Indira Awaas Yojana and MNREGA in Giridih Parliamentary Constituency in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास, मनरेगा के तहत पंचायत भवन का निर्माण हो, चाहे सांसद निधि की बात हो, भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और दामोदर वैली कार्पोरेशन आदि क्षेत्र हैं, यहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत, झारखंड में जब से पंचायत का चुनाव हुआ है, उस क्षेत्र में एक भी इंदिरा आवास का निर्माण नहीं हुआ। उसका कारण है कि वे लोग नो ऑब्जेक्शन नहीं देते। उनका कहना है कि यह हमारी जमीन है, इसलिए हम इसका नो ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। दामोदर वैली कार्पोरेशन की भी यही स्थिति है। इससे वहां जो दलित परिवार के लोग हैं, जो बीपीएल धारी हैं, उनके लिए न तो इंदिरा आवास बन रहा है और न ही मनरेगा का काम हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि गिरिडीह के 16 पंचायत भवनों का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि यदि उनको अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना था, तो वहां पंचायत का चुनाव नहीं होता। सांसद निधि का भी काम नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको डायरेक्शन दिया जाये कि वे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न न करें और अनापत्ति प्रमाण-पत्र दें, ताकि वहां के इंदिरा आवास, पंचायत भवन और मनरेगा के तहत जो विकास कार्य होने हैं, वे हो सकें।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।